

अध्याय: 5

मत्स्य न्याय का समापन: नचिली न्यायपालिका की क्षमता कैसे बढाएं

प्रस्तावना

ज़िला और अधीनस्थ न्यायालयों (District and Subordinate Courts) में कुल लंबति मामलों के 87.54 प्रतिशत मामले हैं, इस अध्याय में इस संदर्भ पर प्रकाश डाला जाएगा तथा नपिटान अवधि, लंबति अवधि, मामलों के प्रकारों और मामला नसितारण दर जैसे मानकों के संबंध में इसके नषिपादन का मूल्यांकन किया जाएगा। इस अध्याय में 100 प्रतिशत नसितारण दर हासलि करने तथा अगले पाँच वर्षों में लंबति मामलों के स्टॉक को समाप्त करने के लयि न्यायालयों के वभिन्न स्तरों पर अतरिकित न्यायाधीशों की आवश्यकता और कार्यक्षमता वर्द्धन का वशिलेषण भी किया जाएगा।

परचिय

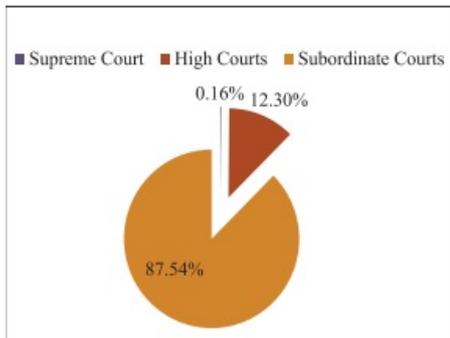
- भारतीय न्यायकि प्रणाली में 3.53 करोड़ से अधिक मामले लंबति हैं।
- भारत के संवधान की उद्देशिका यह परभाषति करती है कि राज्य की प्रथम भूमिका 'इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करना है'। दूसरे शब्दों में, इसे पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाता है कि आर्थिक सफलता और समृद्धि की संवदाओं को लागू करने और वविादो का समाधान करने की सामर्थ्य से काफी अधिक सहबद्धता है।

भारतीय न्याय व्यवस्था (Indian Judicial System):

लंबति मामले

Pendency

Distribution of Pending Cases among different levels of Courts in India



- किसी दी गई तारीख को किसी मामले का लंबति रहना उस मामले को दायर करने की तारीख से उस तारीख तक लगने वाला समय माना जाएगा।
- सभी मामलों में से 64 प्रतिशत से अधिक मामले एक वर्ष से ज्यादा अवधि से लंबति हैं।
- सविलि और आपराधिक दोनों ही प्रकार के मामलों में राष्ट्रीय औसतों की तुलना में ओडिशा, बहिर, पश्चिमि बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात में लंबति मामलों का औसत उच्चतर है जबकि पंजाब और दलिली में लंबति मामलों का औसत सबसे कम है।

नपिटान

Disposal

- मामला दायर करने की तारीख से लेकर नरिणय सुनाए जाने तक की तारीख तक लगने वाले समय को नपिटान समय के रूप में मापा जाता है ।
- 74.7 प्रतशित सविलि मामलों और 86.5 प्रतशित आपराधकि मामलों का नपिटान तीन वर्ष की अवधि के भीतर कर दिया जाता है ।
- सविलि और आपराधकि दोनों मामलों में बहिर, ओडिशि और पश्चमि बंगाल में राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक नपिटान समय लगता है । इसके अलावा, पंजाब और दलिली में औसत नपिटान समय सबसे कम है ।
- जब काउंसलि ऑफ यूरोप के सदस्यों के औसत (2016) की तुलना वर्ष 2018 में भारतीय डीएंडएस न्यायालयों में सविलि और आपराधकि मामलों के लयि औसत नपिटान समय के साथ की गई, तब यह क्रमशः 4.4 गुना था और 6-गुना अधिक था ।

मामला नसितारण दर

Case Clearance Rate (CCR)

- कसिी वर्ष में दायर मामलों की संख्या की तुलना में उस वर्ष में नपिटान कयि गए मामलों की संख्या के अनुपात को मामला नसितारण दर (सीसीआर) कहते हैं । इसे प्रतशित के रूप में दर्शाया जाता है ।
- सीसीआर 2015 में 86.1 प्रतशित की तुलना में 2017 में बढ़कर 90.5 प्रतशित पर पहुंच गई थी, परंतु 2018 में फरि गरिकर 88.7 प्रतशित रह गई ।
- भारत में सविलि मामलों और आपराधकि मामलों के लयि मामला नसितारण दर 2018 में क्रमशः 94.76 प्रतशित और 87.41 प्रतशित थी, जबकि
- सीओई सदस्य 2016 में ही सविलि और आपराधकि दोनों मामलों के लयि 100 प्रतशित से अधिक नसितारण दर हासलि कर चुके थे ।

वधिकि गतरिध को समाप्त करना

Clearing the Legal Logjam

- न्यायपालकिा को अधिकि कार्यक्षम बनाने के लयि फलिहाल दो मुख्य मुद्दों का समाधान करने की आवश्यकता
 - पहला, 100 प्रतशित नसितारण दर हासलि करना ताकि मौजूदा लंबति वादों में आगे कोई वृद्धि न हो ।
 - दूसरा, प्रणाली में पहले से मौजूद मामलों के बैकलॉग को समाप्त करना ।
- वर्तमान दक्षता पर सरल इनपुट-आउटपुट मॉडल का उपयोग करके नमिनलखिति गणना की गई है:

	Supreme Court	High Court	D&S Court
Pendency	56.2 Lakh	40.22 Lakh	3.04 Crore
Case Clearance Rate	98%	88%	89%
Annual Disposal Rate (per judge)	1,179 case	2,348 case	746 case
Additional Judges required to achieve 100% Clearance in a year	1	93	2279
Additional Judges required to clear all backlog in 5 years.	8	361	8,152

भारतीय न्यायालयों को और अधिकि कार्यशील बनाना

दक्षता और रकित्थि भारतीय न्यायकि प्रणाली के प्रदर्शन को प्रभावति करने वाले दो महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं और इसमें सुधार की पर्याप्त गुंजाइश है । इनके अलावा, न्यायपालकिा के प्रदर्शन को बेहतर बनाने हेतु कुछ सुझावों पर नीचे चर्चा की गई है ।

- **कार्य दविसों की संख्या बढ़ाना:** भारतीय अदालतें छुट्टियों के कारण लंबी अवधि के लयि बंद हो जाती हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक वर्ष में केवल 190 दनि काम करता है । कार्य दविसों की संख्या बढ़ाकर सर्वोच्च न्यायालय और कुछ उच्च न्यायालयों के प्रदर्शन में महत्त्वपूर्ण सुधार कयि जा सकता है, जबकि इस नरिणय से नचिली अदालतों के अप्रभावति रहने की संभावना है क्योंकि उनके औसत कार्य दविस लगभग सरकारी वभिगों के समान ही हैं ।
- **भारतीय न्यायालयों और अधिकिरण सेवाओं की स्थापना:** अधिकतर न्यायकि सुधारों का रुझान न्यायाधीशों की गुणवत्ता और संख्या पर ही वशिष ध्यान देने वाला रहा है, परंतु प्रमुख समस्या न्यायालयों की प्रणाली, प्रमुखतया अनुषंगी एवं अप्रत्यक्ष कार्यप्रणालियों और प्रक्रयिओं के प्रशासन की गुणवत्ता से सहबद्ध है । वर्तमान प्रणाली में, भारतीय न्यायालयों में प्रशासन की मुख्य जमिमेदारी मुख्य न्यायकि अधिकारी को सौपी गई है । उसके पास इस कार्य के लयि अत्यधिक कम समय होने के अलावा, यह अवधारणा प्रणालीगत सुधारों और प्रशासनकि सुधारों संबंधी संस्थागत ज्ञान के क्रमकि संचय में सहायक नहीं है । इस संदर्भ में, भारतीय न्यायालय और अधिकिरण सेवा (आईसीटीएस) नामक वशिषिट सेवा का सृजन करने का

